SHRI B. V. NAIK: Is the hon. Minister aware that in some of the cities like Bangalore already diesel oil is being informally rationed out at the rate of about 10—15 litres per truck with a capacity of 100 litres and there has already started an incipient black market in diesel oil at higher prices?

SHRI D. K. BAROOAH: It is true that there is a shortage all over. It is within the authority of State Governments and also their responsibility to ration, if they so desire. But I think that wherever there is a shortage, some kind of premium marketing also takes place.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: For more production in our own country, is the Minister having any plan to have off-shore drilling?

SHRI PILOO MODY: Deep sea drilling.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: No, off-shore drilling.

SHRI D. K. BOROOAH: Yes, Sir.

पांचवीं योजना में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये विदेशों से सहायता

-I-

*751. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री पांचवी योजना के दौरान उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3876 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पचवर्षीय योजना के दौरान 11 उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना के दौरान उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये लिये कितनी विदेशों में कितनी सहायता मांगी अथवा आवश्यकता होगी तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे सहायता प्राप्त की जा रही है ; और

(ग) इन कारखानों की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): (a) Details regarding additional fertilizer capacity required to be set up during the Fifth Plan Period are being worked out. It seems that about 10—12 new plants would have to be set up to meet the projected level of demand by 1978-79.

(b) M/s. Engineers (India) Limited have submitted a proposal for setting up of five fertilizer plants with Japanese cooperation and credit. The foreign exchange requirements for these plants are estimated at $220 million. Government of Japan have been approached for extending the necessary credit facilities in this regard.

The foreign exchange requirements of the remaining fertilizer plants along with the possible sources of financing are being worked out separately.

(c) The capacity envisaged, at present, for the new plants is of the order of 900 tonnes/day ammonia for inland locations and 1,300 tonnes/day ammonia in coastal locations.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया दस या बारह। कोई निश्चित जवाब नहीं है कि दस हो या बारह हो। मुझे यह जानना है कि जापान के सिवाय क्या और किसी देश ने मदद करने का आश्वासन दिया है और जापान ने जितने कारखाने लगाने में आपको मदद देने का आश्वासन दिया है? जापान के सिवाय और किसी देश से मदद नहीं मिलती है तो अपने देश में अपनी ताकत से वे दस या बारह कारखाने लगाने की क्षमता क्या आप रखते हैं या नहीं?

श्री देवकान्त बरुआ : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने जो पूछा है कि जापान का छोड़कर दूसरे किसी और मुल्क के साथ कुछ इसके बारे में चर्चा हुआ या नहीं तो चर्चा तो हुआ है ....

श्री विभूति मिश्र : वह कौन कौन से देश है?

श्री देवकान्त बरुआ : इंग्लिस्तान भी हुआ है, साइमन कार्ब्ज, हम्फ्रीज, ग्लासगो से भी बात चल रही है और फ्रेंच इस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम से भी बात चल रही है। तीन और मुलकों ने भी इसके बारे में कुछ आग्रह दिखाया है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है।

दूसरी बात यह है कि दस बारह जो हैं तो दस भी हो सकता है, बारह भी हो सकता है और उसके बीच के समन्वय में 11 भी हो सकता है।

जहां तक प्रश्न है कि हम स्वयं इन कारखानों को बनायें—इसके बारे में हमारे पास टैक्नोलोजी है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास टैक्नोलोजी नहीं है। लेकिन 10—12 कारखाने बनेंगे, इसलिये कारखानों के वास्ते नई टैक्नोलोजी भी चाहिये साधजन भी चाहियें, फौरन-एक्सचेंज भी चाहिये, इसलिये हम चाहते हैं कि हम अपनी टैक्नालोजी और बाहर से जो मदद और टैक्नालोजी मिलेगी, उनका समन्वय करके इंजन कारखानों को लगायें।

श्री विभूति मिश्र इस सदन में अगले महीने पांचवी पंच वर्षीय योजना पर चर्चा होगी—ऐसा सरकार ने मान लिया है। अगली पंचवर्षीय योजना में खेती में सरकार जो उत्पादन चाहती है, उसको दृष्टि में रखते हुये फर्टिलाइजर कारखाने लगाने का काम फौरन शुरू होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय आपको भी अनुभव होगा, क्योंकि पंजाब हिन्दुस्तान में खेती के मामले में सिरमौर है, हमारे पास जितना फर्टिलाइजर है और जितने फर्टिलाइजर की क्षमता हम चाहते है—इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने ये कागजी प्लान बनाये है या वास्तविक प्लान बनाये हैं। यदि वास्तविक बनाये हैं तो इस प्लान के द्वारा कब तक फर्टिलाइजर पैदा करके पांचवी पंच वर्षीय योजना के सफलीभूत करने बात सोच रहे हैं?

श्री देवकान्त बरुआ : पांचवीं पंचवर्षीय योजना की तो अभी शुरुआत नहीं हुई है ....

श्री विभूति मिश्र : अगले साल होगी ।

श्री देवकान्त बरुआ : हां, अगले साल होगी । इसके लिये जो सिद्धान्त तय किया गया है, वह सही है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना के अन्दर ही उसको बनाया जायगा । जब पांच साल का समय रखा गया है तो मेरे खयाल में पांच साल में यह काम समाप्त हो जायेगा ।

SHRI MOHANRAJ KALINGARAYAR: Will the hon. Minister tell us, out of these 10, 11, 12 or 13 fertiliser plants that are going to be set up, which are the States in which these fertiliser plants are going to be set up, and how many fertiliser plants will be set up in Tamil Nadu?

SHRI D. K. BOROOAH: We have only planned for five just at this moment. Out of these five, three will be based on fuel oil produced by the Mathura refinery. One will be in Mathura itself; another will be at Bhatinda in Punjab; and the third one would be in Haryana, either in Karnal or in Panipat.

Two plants would be located on the sea-coast, and for this, we have found that the eastern coast needs more fertiliser factories. Therefore, it has been decided to set up one in Paradip, which is a good port. For the other, Kakinada is one of the names which is being very favourably considered.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I would like to know from the hon. Minister whether the Government will be in a position to meet the requirements of fertilisers at the end of the fifth Plan?

SHRI D. K. BOROOAH: I think it will be a happy day if our fertiliser supplies remain behind the requirements, for, that will indicate that our cultivators are up and doing and are so progressive that it will be difficult to meet their demands.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: That shows your inefficiency.

SHRI D. K. BOROOAH: Not necessarily. It shows that our cultivators are up and doing and are progressive.

SHRI JAGANNATH RAO: The Minister was pleased to say that one of the fertiliser units would be located at Paradip in Orissa. I would like to know what is the annual capacity of this unit and when the construction of it is likely to start.

SHRI D. K. BOROOAH: As I have said earlier, the coastal fertiliser factory will produce 1,300 tonnes of ammonia per day.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Keeping in view the Government of India's policy and their approach to remove the regional imbalances, may I know from the hon. Minister whether he will deeply consider the matter to set up some of the fertiliser factories in the backward regions of the country, and of course one should be in the North Bengal area?

SHRI D. K. BOROOAH: Certainly the removal of regional imbalances is a necessity which cannot be overlooked. I also agree that North Bengal is a somewhat backward part of the advanced States of West Bengal.

SHRI SAMAR GUHA: In view of the objective of our Fifth Plan to achieve a self-reliant economy, is the Government going to utilise the know-how and technology, engineering and design capacity and technocrat management that has been developed by the Fertiliser Corporation of India very successfully, before taking foreign assistance from foreign collaborators as had been done in the

case of Toyo and also utilise the possibilities of the planning and development division of the Fertiliser Corporation?

SHRI D. K. BOROOAH: Yes, Sir.

श्री नाथू राम मिर्धा : आपने जिन 10–12 यूनिट को लगाने के बारे में बतलाया है, मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो फास्टफेट और पाइराइट्स का अतुल भण्डार है उसके उपयोग के बारे में भी विचार किया है ? आज फास्फेट फर्टिलाइजर इम्पोर्ट किए जाते हैं, उस इम्पोर्ट को रोकने की दृष्टि से क्या राजस्थान के इन मिनरल्ज के उपयोग करने की बात ख्याल मे रखी गई है ?

श्री देवकान्त बरुआ : राक-फास्फेट के बारे मे एक विशेष चर्चा हो रही है । इसमें कोई सन्देह नही है कि राजस्थान मे राक-फास्फेट और पाइराइट्स का काफी भ डार है, लेकिन यह काम क्या रूप लेगा, इस बारे में अभी कुछ कहना मेरे लिये सम्भव नही होगा ।

Lease of Fallow Land along Railway track to Railway Employees for Growing Food Crops

*752 SHRI J G. KADAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the former Railway Minister had announced in Lok Sabha that the fallow land along the Railway tracks will be given on temporary lease to the Railway employees for growing food crops;

(b) if so, how many hectares of such land was given on lease in the years 1971-72 and 1972-73 and how many employees have taken the advantage of the scheme; and

(c) what is the result of this scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes Sir, the former Railway Minister had announced that the surplus cultivable railway land will be used for grow more food and other purposes by allotting such land to Railway employees.

(b) and (c). The information i being collected and will be placed on the table of the House.

SHRI J. G. KADAM: How much time will the hon. Minister need for placing the information on the Table of the House?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I cannot give a definite date but I think the beginning of the next session.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सच है कि भूतपूर्व रेल मंत्री की इस प्रकार की घोषणा के बावजूद 1971–72 और 1972–73 मे गैर रेलवे मजदूरों को भी रेलवे की इस तरह की जमीन लीज पर दी गई है ? अगर दी गई है तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ऐसा हो सकता है कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी जमीन दी गई है । इसमें कोई शक नही है कि कुछ जमीन सूबाई सरकारो को दी गई हैं, उन्होने उसका इस्तेमाल किया है और कुछ जमीन उन लोगों को भी दी गई है जो रेलवे के मुलाजिम नही है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व रेल मंत्री ने जो नीति निर्धारित की थी, उसमें केवल रेल मजदूरों और रेल